DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से है रेवेन्यू कमाने की तैयारी

■ **विस, नई दिल्ली :** रेवेन्यू बढ़ाने के लिए डीडीए अब क्लब के साथ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स योजना पर काम कर रहा है। डीडीए के मुताबिक ऐसा कर वह अपने इन्फ्रास्ट्रक्चर का बेहतर इस्तेमाल कर पाएगा। इसकी शुरुआत द्वारका सेक्टर-17 के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से होगी। इसके बाद इसे द्वारका सेक्टर-19, 23 और आठ के अलावा रोहिणी के सेक्टर-33 के स्पोर्ट्स कॉप्लेक्स में भी इसे लाया जाएगा।

डीडीए अधिकारी के अनुसार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में रेस्टोरेंट, ओपन बैंक्विट, रेस्टोरेंट और बार की जगह को वह लीज करेगा। इन जगहों का इस्तेमाल वो लोग भी कर सकेंगे, जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के मेंबर नहीं हैं। जो लोग खेल एक्टिविटी से नहीं जुड़े हैं, वह भी इस जगह पर आकर सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के सदस्य भी अपने मेहमानों को यहां लेकर आ सकते हैं। सीनियर सिटिजंस को भी अपने घरों के पास गेट टुगेटर के लिए जगह मिलेगी। डीडीए के अनुसार द्वारका सेक्टर-17 का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 23 एकड़ में बना हुआ है। इंडोर और आउटडोर स्टेडियम जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, स्क्वैश, बॉक्सिंग और टेबल टेनिस आदि की सुविधा यहां है। डीडीए के प्लान के अनुसार इस कॉम्प्लेक्स के एंट्रेंस पर बनी कैंटीन एरिया को रेस्टोरेंट कम बार में बदलने का प्लान है। वहीं टैरेस पर बैंक्वेट सुविधा शुरू करने की प्लानिंग है। इसके साथ ही स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के सामने खाली लॉन पर भी बैंक्विट की योजना है।

कॉम्प्लेक्स में बनेंगे रेस्टोरेंट, टैरेस बैंक्विट, पार्टी और कॉन्फ्रेंस रूम

द्वारका: पेड़ों की छंटाई नहीं

■ **विस, द्वारका:** द्वारका सेक्टर-22 के डीडीए एसएफएस पॉकेट में लोग पेड़ों की छंटाई नहीं होने से परेशान हैं। लोगों का कहना है कि शिकायत करने के बावजूद पिछले कई महीनों से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।

एनबीटी सुरक्षा कवच ग्रुप से जुड़े द्वारका सेक्टर-22 डीडीए एसएफएस पॉकेट के सेकेटरी राकेश शर्मा ने बताया कि उनकी सोसायटी में 70 से 100 बड़े पेड़ हैं। इनमें से अधिकांश पीपल और पिलखन के हैं। करीब पांच साल पहले पिलखन का एक पेड़ गिरने से एक गार्ड की मौत हो चुकी है। हादसों को रोकने के लिए हर साल इन पेड़ों की छंटाई होती है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से बार बार आवेदन करने के बावजूद एमसीडी/हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट इनकी छंटाई नहीं कर रहा है।

NBT सुरक्षा कवच
मिलकर बनाएं दिल्ली को ज्यादा सेफ

। नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । शुक्रवार, 8 दिसंबर 202 ----------DATED----------

DDA जमीन पर कब्ज़ा, MCD का चला बुलडोज़र

■ **विस, नई दिल्ली:** एमसीडी के सिविल लाइंस जोन ने बुराड़ी की बाबा कॉलोनी में चल रहे अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया। पुलिस बल की मौजूदगी में एमसीडी की टीम ने बुलडोजर की मदद से कृषि भूमि पर चल रहे अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। एमसीडी अधिकारियों ने बताया कि बाबा कॉलोनी में कृषि भूमि पर लंबे समय से अवैध निर्माण चल रहा है। गुरुवार को एमसीडी की टीम दल बल के साथ मौके पर पहुंच गई। जिस समय एमसीडी की टीम वहां पहुंची उस समय भी गोदामों को बनाने के लिए दर्जनों कर्मचारी काम कर रहे थे। एमसीडी के बुलडोजर ने एक एक करके अवैध निर्माण को ध्वस्त किया।

दैनिक जागरण नई दिल्ली, 8 दिसंबर, 2023

नवंबर तक पूरा होना था प्रोजेक्ट, नई डेडलाइन अब जनवरी 2024

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) के तहत निर्माण कार्य पर लगी रोक का असर दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के जेलरवाला बाग प्रोजेक्ट पर भी पड़ा है। यहां बन रहे ईडब्ल्यूएस श्रेणी के फ्लैट अपने तय समय से थोड़ा देरी से पूरा होंगे। इस प्रोजेक्ट को नवंबर के अंत तक पूरा किया जाना था, लेकिन अब इसके जनवरी 2024 तक पूरा होने की संभावना है।

अधिकारियों के अनुसार ग्रेप तीन और चार की पाबंदियों की वजह से इस प्रोजेक्ट का काम भी प्रभावित हुआ। अधिकारी के अनुसार पहले डीडीए दीवाली पर इन फ्लैटों का कब्जा देने की तैयारी में था। लेकिन ग्रेप के चलते इसका काम रुक गया। इस समय यहां कुछ फिनिशिंग वर्क पूरे किया जा रहे हैं, जिसे पूरा करने में करीब एक महीने का समय और लग सकता है। इसके बाद ही फायर एनओसी लेने की प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। मालूम हो कि, दिल्ली में यह दूसरा इन सीटू प्रोजेक्ट है। नवंबर 2022 में पीएम नरेंद्र मोदी ने कालकाजी में लाभार्थियों को इसी तरह के 3024 फ्लैट सौंपे थे। यह सारे फ्लैट ईडब्ल्यूएस के लिए बनाए जा रहे हैं और डीडीए की जहां झुग्गी वहीं मकान योजना में शामिल हैं। जेलरवाला बाग में कुल 1675 फ्लैट बन रहे हैं। इनमें से अशोक विहार के 1063 झुग्गी वालों को यह मकान इसी साल अप्रैल में आवंटित किए गए थे। बाकी बन रहे फ्लैटों के लिए इस प्रोजेक्ट साइट के पांच किमी दायरे में बने दो क्लस्टर से अन्य लाभार्थियों का चयन किया जा रहा है। अधिकारी के अनुसार लाभार्थियों के सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है। एलजी वी के सक्सेना के निर्देश के बाद डीडीए ने जुलाई में एक सुविधा केंद्र की शुरुआत की थी। इस केंद्र में आवंटियों को दस्तावेज तैयार करने में मदद की जा रही है।

डीडीए के अनुसार यह प्रोजेक्ट 421.8 करोड़ का है। हर फ्लैट पर डीडीए 24 लाख रुपये के करीब की सब्सिडी दे रहा है। इन फ्लैट में दो कमरे, रसोई, बाथरूम और शौचालय शामिल हैं।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS- दैनिक जागरण नई दिल्ली, 8 दिसंबर, 2023 DATED----------

किराये के भवनों में चल रहे दिल्ली के 13 थाने

लोकसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने 225 में से 13 थाने किराये की इमारत में चलने की बात की

राकेश कुमार सिंह • नई दिल्ली

राजधानी के 225 में 13 थाने किराये की इमारतों में चलने का मामला बुधवार को लोकसभा में भी उठा, जिससे माना जा रहा है पुलिस विभाग अब अपनी जमीन पर थानों का निर्माण करने की दिशा में प्रयास तेज कर सकता है। राजधानी की आबादी जैसे-जैसे बढ़ती जा रही है, बेहतर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिल्ली पुलिस को नए थाने भी खोलने पड़ रहे हैं। कई थानों को जमीन न मिल पाने के कारण वे अब तक किराये की इमारतों में ही चल रहे हैं। ऐसे थानों में सुविधाओं का घोर अभाव रहता है, जिससे कामकाज में अड़चन आती ही है, साथ ही महिला पुलिसकर्मियों को सर्वाधिक परेशानी उठानी पड़ती है। किराये पर भी भारी खर्च करना पड़ रहा है। ये थाने तीन से साढ़े सात लाख रुपये मासिक किराये पर चल रहे हैं।

सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी के आधार पर दैनिक जागरण ने 18 अगस्त को दिल्ली पुलिस के 13 थाने किराये की इमारतों में चलने की खबर प्रकाशित की थी। कई थाने को खोले हुए 15 साल से भी अधिक समय बीत चुका है, लेकिन उन्हें अब तक अपने भवन के लिए जमीन नहीं मिल पाई है। पुलिस अधिकारी के मुताबिक सरकारी विभागों में तालमेल के अभाव के कारण ऐसा हो रहा है। थानों के लिए जमीन प्राप्त करने के लिए पुलिस विभाग डीडीए और एमसीडी के अलावा दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग से ग्राम सभा व कृषि भूमि के लिए वर्षों से चक्कर काट रहा है, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल पा रही है। जमीन न मिल पाने के कारण बड़ी संख्या में ऐसे भी थाने हैं, जहां दो थाने एक ही परिसर में चल रहे हैं। उदाहरण के तौर पर मंडावली और मधु विहार थाने एक ही बिल्डिंग में चल रहे हैं। इसी तरह सरोजनी नगर और सफदरजंग एन्क्लेव थाने एक ही परिसर में है।

हर साल दिल्ली पुलिस को मिलने वाले बजट में करोड़ों रुपये नए थानों के भवन निर्माण और पुलिसकर्मियों के आवासीय कालोनियों के लिए मिलते हैं, लेकिन उक्त रकम पुलिस विभाग उस मद में खर्च नहीं कर पा रहा है। कुछ थानों को जमीन मिली भी है, तो वह पर्याप्त नहीं है। जिससे वहां भवन का निर्माण नहीं हो पा रहा है। ऐसे थाने पोटा केबिन में ही चल रहे हैं। वहां अधिकारियों तक को बैठने में असुविधा होती है। पुलिस अधिकारी का कहना है कि इस बार के बजट में दिल्ली पुलिस को 11932.03 करोड़ रुपये दिए गए। अगर पुलिस विभाग को संबंधित सरकारी विभागों के सहयोग से जमीन मिल जाती तब थानों की इमारतों का निर्माण किया जा सकता था। मजबूरी में विभाग को थानों का किराया भरना पड़ रहा है। यही हाल दिल्ली मेट्रो थाने का है। दिल्ली पुलिस को मेट्रो के 16 थाने खोलने पड़े। संयोग से डीएमआरसी ने सभी थानों को अपनी जगह मुफ्त में मुहैया कराई है। मेट्रो पुलिस के डीसीपी का कार्यालय भी कश्मीरी गेट पर पोटा केबिन में ही चल रहा है।

किराये की इमारत में चल रहा है दिल्ली का रणहौला थाना • जागरण

दिल्ली के ये थाने 55 हजार से 7.56 लाख रुपये तक दे रहे किराया

थाने का नाम	जिले का नाम	मासिक किराया (रुपये लाख में)
शाहबाद डेरी	बाहरी-उत्तरी	2
भलस्वा डेरी	बाहरी-उत्तरी	2.11
स्वरूप नगर	बाहरी-उत्तरी	1.29
भारत नगर	उत्तर-पश्चिम	0.77
प्रेम नगर	रोहिणी	1.45
जैतपुर	दक्षिण-पूर्वी	7.56
सोनिया विहार	उत्तर-पूर्वी	2.21
फतेहपुर बेरी	दक्षिण	2.13
छावला	द्वारका	0.55
करावल नगर	उत्तर-पूर्वी	2.20
निहाल विहार	बाहरी	3.19
रणहौला	बाहरी	1.55